वाणिज्य और उद्योग शोषस्थ और क्षेत्रीय निकायों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया। इसके अतिरिक्त चीन के प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में दिल्ली में हुआ भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेला देखा और विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों के पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों की यूनिटें भी देखीं। इन विचार-विमर्शों में, जो कि अपने आप में अन्वेषी प्रकृति के थे अतिथि और आतिथ्य निगमों और निरीक्षित यूनिटों के नानाविध क्रियाकलापों पर तथा उनके द्वारा आयातित और निर्यातित मदों के स्वरूप पर द्विपक्षीय व्यापार के विकास में पारस्परिक हित के क्षेत्र तय करने की दृष्टि से विचार किया गया।

(ख) और (ग). सरकार को अभी यात्री-दलों द्वारा इंजीनियरी का सामान बुक किए जाने के विशिष्ट आर्डरों के विषय में तो जानकारी नहीं है लेकिन यह समझा जाता है कि वे भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई उच्चस्तरीय उन्नति से बहुत प्रभावित हुए हैं। उत्पादन क्षेत्र की कई ऐसी चीजें तय हुई हैं जिन का चीन बहुत बड़ा आयातक है और इस आकलन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत इन मदों की आपूर्ति करने की स्थिति में है।

Delegation of Journalists to visit China

2160. SHRI G. TOHRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether People's Republic of China has invited a delegation of Indian Journalists to visit China;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the criteria laid down, if any, to select the journalists to visit China?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): (a) and (b). The Ambassador of China in India has extended an invitation on behalf of the Hsinhua news agency of the People's Republic of China to send a group of 3—5 Indian journalists for a friendly visit to China in March/April this year. The invitation has been accepted.

(c) The matter is receiving attention.

विदेशों के कब्जे में भारतीय भूमि-क्षेत्र

2161. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 की सीमा रेखा के अन्दर भारतीय भूमि के कितने क्षेत्र पर विदेशों ने गैर-कानूनी कब्जा किया हुआ है और किन-किन देशों ने; और

(ख) क्या सरकार इस भूमि को खाली कराने के लिये इन देशों के साथ वार्ता कर रही है और यदि हां, तो इस वार्ता का आधार क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जम्मू और काश्मीर राज्य के प्रदेश का लगभग 30,200 वर्ग मील क्षेत्र 1947–48 से ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का लगभग 2000 वर्ग मील का इलाका भी पाकिस्तान ने 1963 के तथा कथित चीन-पाक समझौते के अन्तर्गत चीन को गैर-कानूनी रूप से दे दिया है।

भारत-चीन सीमा के लद्दाख सेक्टर में भारतीय क्षेत्र का लगभग 14,500 वर्गमील का इलाका चीन के कब्जे में है।

(ख) भारत सरकार की नीति यह है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जे में किये गए क्षेत्र को खाली कराने के प्रश्न को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए।